

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 3

PART I—Section 3

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं.	02]	नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 9, 2019/पौष 19, 1940
No.	02]	NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 9, 2019/PAUSHA 19, 1940

गृह मंत्रालय

(पूर्वोत्तर प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 जनवरी, 2019

सं 11012/06/1995-एन.ई.IV.—असम समझौता के नाम से एक समझौता ज्ञापन पर दिनांक 15 अगस्त, 1985 को हस्ताक्षर किए गए। समझौते के खण्ड 6 में यह कहा गया है कि :

"असमिया लोगों की सांस्कृतिक, सामाजिक, भाषाई पहचान और विरासत को संरक्षित, परिरक्षित और संवर्धित करने के लिए यथा उपयुक्त, संवैधानिक, विधायी एवं प्रशासनिक सुरक्षोपाय प्रदान किए जाएंगे।"

2. तदनुसार, एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने का निर्णय लिया गया है जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

(i)	श्री एम.पी. बेजबरुआ, आईएएस (सेवानिवृत्त)	-	अध्यक्ष
(ii)	श्री सुभाष दास, आईएएस (सेवानिवृत्त)	-	सदस्य
(iii)	डॉ. नागेन सैकिया, पूर्व अध्यक्ष, असम साहित्य सभा	-	सदस्य
(iv)	श्री धीरेन बेजबरुआ, द सेंटिनेल के पूर्व सम्पादक	-	सदस्य
(v)	डॉ. मुकुन्द राजबंशी, शिक्षाविद्	-	सदस्य
(vi)	श्री रमेश बोरपात्रागोहेन, महाधिवक्ता, असम	-	सदस्य
(vii)	श्री रोंगबोंग तेरांग, पूर्व अध्यक्ष, असम साहित्य सभा	-	सदस्य
(viii)	ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन का एक प्रतिनिधि	-	सदस्य
(ix)	संयुक्त सचिव, गृह मंत्रालय	-	सदस्य सचिव

184 GI/2019 (1)

- 3. समिति के विचारार्थ विषय निम्नलिखित हैं:-
 - (क) समिति असम समझौते के खण्ड 6 को कार्यान्वित करने के लिए वर्ष 1985 से की गई कार्रवाइयों की प्रभावकारिता की जांच करेगी।
 - (ख) सिमिति सामाजिक संगठनों, विधिक और संवैधानिक विशेषज्ञों, कला, संस्कृति एवं साहित्य के क्षेत्र में प्रतिष्ठित व्यक्तियों, संरक्षणवादियों, अर्थशास्त्रियों, भाषाविदों और समाजशास्त्रियों सहित विभिन्न हितधारकों के साथ चर्चा करेगी।
 - (ग) सिमिति असिमया लोगों के लिए असम विधान सभा तथा स्थानीय निकायों में सीटों के आरक्षण के उपयुक्त स्तर का आकलन करेगी।
 - (घ) सिमिति असमी और असम की अन्य स्थानीय भाषाओं को संरक्षित करने के लिए किए जाने वाले उपायों का भी सुझाव देगी।
 - (इ.) सिमिति असिमया लोगों के लिए असम सरकार के अंतर्गत रोजगार में आरक्षण के उपयुक्त स्तर की सिफारिश करेगी।
 - (च) सिमिति असिमया लोगों की सांस्कृतिक, सामाजिक, भाषाई पहचान और विरासत को सुरक्षित, संरक्षित और संवर्धित करने के लिए आवश्यक अन्य उपायों का सुझाव देगी।
- 4. सिमति अधिसूचना की तारीख से 6 माह के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।
- 5. समिति को गृह मंत्रालय, भारत सरकार के एन.ई. प्रभाग द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी।
- 6. असम राज्य सरकार समिति को आवश्यक प्रशासनिक और संभारतंत्र सहायता प्रदान करेगी।

सत्येन्द्र गर्ग, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(North East Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th January, 2019

No. 11012/06/1995-NE.IV.—A Memorandum of Settlement, known as the Assam Accord was signed on 15th August, 1985. Clause 6 of the Accord states that:

"Constitutional, legislative and administrative safeguards, as may be appropriate, shall be provided to protect, preserve and promote the cultural, social, linguistic identity and heritage of the Assamese people."

2. Accordingly, it has been decided to constitute a High Level Committee comprising the following:

Shri M.P. Bezbarauah, IAS (Retd.) (i) Chairman (ii) Shri Subhash Das, IAS (Retd.) Member (iii) Dr. Nagen Saikia, Member Former President, Assam Sahitya Sabha (iv) Shri Dhiren Bezbaruah, Member Former editor of The Sentinel Dr. Mukunda Rajbangshi, Member (v) Educationalist Shri Ramesh Borpatragohain, Member (vi) Advocate General, Assam

(vii) Shri Rongbong Terang, - Member Former President, Assam Sahitya Sabha

- (viii) One representative of
 - All Assam Students' Union
- (ix) Joint Secretary, MHA Member Secretary
- 3. The Terms of Reference for the Committee are as under:-
 - (a) The Committee will examine the effectiveness of actions taken since 1985 to implement Clause 6 of the Assam Accord.

Member

- (b) The Committee will hold discussions with various stakeholders including social organizations, legal and constitutional experts, eminent persons from the field of art, culture and literature, conservationists, economists, linguists and sociologists.
- (c) The Committee will assess the appropriate level of reservation of seats in Assam Legislative Assembly and local bodies for the Assamese people.
- (d) The Committee will also suggest measures to be taken to protect Assamese and other indigenous languages of Assam.
- (e) The Committee will recommend the appropriate level of reservations in employment under the Government of Assam for the Assamese people.
- (f) The Committee may suggest any other measures as may be necessary to protect, preserve and promote cultural, social, linguistic identity and heritage of the Assamese people.
- 4. The Committee will submit its report within 6 months from the date of notification.
- 5. The Committee will be serviced by the NE Division of MHA, Government of India.
- 6. The State Government of Assam will provide necessary administrative and logistic support to the Committee.

SATYENDRA GARG, Jt. Secy.